

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2078
जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....
तमिलनाडु में भूजल की स्थिति

2078. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि तमिलनाडु में जल स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया है और कुछ स्थानों पर यह सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है;
- (ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि तमिलनाडु सहित भारत में कई शहरों में भूजल निष्कर्षण और पुनर्भरण के बीच बेमेलपन में वृद्धि हुई है; और
- ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा तमिलनाडु में भूजल के पुनर्भरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश में प्रेक्षण कुओं के नेटवर्क के जरिए क्षेत्रीय पैमाने पर भूमि जल की निगरानी करता है। पूर्व मॉनसून जल स्तर आंकड़े (2018) के अनुसार तमिलनाडु में जल स्तर की आम गहराई 2-10 मीटर के बीच है। लेकिन अलग-थलग पॉकेटों, मुख्य रूप से कोयम्बटूर और कुड्डालूर जिलों में भूमि जल स्तर की गहराई (भूमि से 40 मीटर से अधिक नीचे) भी देखी गई है।

दीर्घावधि आधार पर जल स्तर में कमी/वृद्धि के आकलन के लिए पूर्व मॉनसून जल स्तर आंकड़े 2018 की दशकीय औसत (2008-2017) जल स्तर से तुलना की गई है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि तमिलनाडु राज्य में निगरानी किए जा रहे लगभग 60 प्रतिशत कुओं में भूमि जल स्तर घटा है और 40 प्रतिशत कुओं में बढ़ा है।

विभिन्न उपायों के लिए स्वच्छ जल की बढ़ती मांग, वर्षों में विविधता, अधिक आबादी, औद्योगीकरण और शहरीकरण के चलते भूमि जल की लगातार निकासी, कम वर्षों के कारण पुनर्भरण की कम मात्रा उपलब्ध होने से देश के विभिन्न हिस्सों में भूमि जल स्तर कम हो रहा है।

(ग) जल, राज्य का विषय होने के नाते भूजल के पुनर्भरण सहित जल प्रबंधन के लिए प्रयास करना प्राथमिक रूप से राज्यों का दायित्व है। अन्य प्रयासों में तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय समुदायों द्वारा जल निकायों के निमोण और रख-रखाव के लिए 'कुडीमारमथ' नामक जल स्कीम शुरू की है।

माननीय प्रधान मंत्री ने जल संरक्षण और संग्रहण के महत्व के विषय में सभी सरपंचों को दिनांक 08.06.2019 को पत्र लिखा है और उनसे आह्वान किया है कि वे जल संरक्षण को एक जल आंदोलन बनाने के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनाएं।

भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया , जो मिशन मोड विचारधारा के साथ ए समयबद्ध अभियान है, जिसका उद्देश्य जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूमि जल दशाओं समेत जल उपलब्धता में सुधार करना है।

भूमि जल में कमी को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अन्य उपा निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf
